नव भारत, भोपाल
24 JUN 2011

कृषि केबिनेट

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की खेती के लिये दो लक्ष्य 1. खेती को लाभ का धंधा बनाना और 2. राज्य को जैविक खेती पर लाना निर्धारित किये हैं. इनके क्रियान्वयन के लिये अब मंत्रिमंडल की कृषि क्षेत्र समिति गठित की है- जिसे कृषि केबिनेट के नाम से जाना जायेगा. कृषि के विकास के लिए जो सघन प्रयास हो रहे हैं उससे मध्यप्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश का सर्वप्रथम कृषि राज्य बन सकता है. कृषि केबिनेट में ऐसे 12 मंत्री हैं जिनके अन्तर्गत 34 विभाग आते हैं और उनका कृषि विकास से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध रहता है. मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके अध्यक्ष होंगे.

राज्य में कृषि व वन क्षेत्र बहुत हैं. इसका विकास व संरक्षण दोनों ही अति राष्ट्रीय महत्व के हैं. हाल की विश्व घटनाओं व अर्थ व्यवस्था ने स्पष्ट कर दिया है अन्य सभी औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि से सर्वोपरि कृषि की प्रगति व खाद्यान्न का उत्पादन है. अब विश्व अर्थ व्यवस्था का आधार ही कृषि हो गया है.

मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन में हमेशा से देश में प्रथम रहा. अब दालों के उत्पादन में देश के उत्पादन का एक चौथाई भाग पैदा कर सबसे आगे है. मध्यप्रदेश में गेहूं की बम्पर फसल आती है और उसकी किस्म भी मंडियों में श्रेष्ठ मानी जाती है. निमाड़ में कपास और चम्बल में सरसों का खूब उत्पादन हो रहा है.

मध्यप्रदेश में बिजली का और सिंचाई का काफी अभाव है. श्री चौहान का यह संकल्प भी है कि राज्य में 2013 तक भरपूर बिजली मिलेगी. राज्य में सिंचाई का रकबा 34-35 प्रतिशत का है. नर्मदा घाटी के बांधों व अन्य विकसित किये जा रहे कार्यों से यह प्रतिशत भी बढ़ेगा. कृषि केबिनेट के केन्द्रित प्रयासों से राज्य में कृषि निश्चित ही लाभ का धंधा हो जायेगी.